मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय विकास बोर्डों का गठित किया जाना

3308. **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस प्रकार महाराष्ट्र में क्षेत्रीय विकास बोर्ड गठित किये जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए वैसे ही क्षेत्रीय विकास बोर्डों के गठित किय जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य में क्षत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या पहल की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) भारत सरकार का विचार है कि किसी राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को योजना बनाकर शीघ्र विकास द्वारा हल किया जाना चाहिए । इस मामले में कार्रवाई करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का कार्य है ।

सिनेमा उद्योग पर आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रतिकूल प्रभाव

3309. **श्री अजीत जोगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कारण सिनेमा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और विभिन्न शहरों में बहुत से सिनेमाघर बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सिनेमा उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान बन्द हुए सिनेमाघरों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेंद्र) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी थी । इसने विभिन्न रियायतों/सहायता आदि के रूप में फिल्म उद्योग के लिए 59 सिफारिशें की हैं जैसे 1. मनोरंजन कर 2. उत्पाद शुल्क 3. सिनेमा उपकरणों पर सीमा शुल्क और 4. फिल्में कच्चे माल की सप्लाई में रियायत/राहत, 5. रियायती संस्थागत वित्त, 6. टेलीविजन और रेडियो पर फीचर फिल्मों, गीतों इत्यादि के प्रसारण के लिएअधिक रायल्टी और 7. वीडियो चोरी इत्यादि को रोकने के लिए वीडियो प्रदर्शनों को लाइसेंस देना और उनका नियंत्रण करना । सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण 1 में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र सं० 113] सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और संबंधित प्राधिकारियों को कार्यरूप देने के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) फिल्म प्रभाग के वितरण शाखा कार्यालयों में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1989–90 के दौरान कुल 321 सिनेमा घर बन्द किए गए । तथापि, इसी अवधि में, विभिन्न राज्यों में 117 नए सिनेमाघर खोले गए अथवा फिर से चालू किए गए । बन्द किए गए